ई-न्यूज

24 न्यूज अपडेट

WebSite.: https://24newsupdate.in

उदयपुर, बुधवार 23 जुलाई 2025

Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com

वर्ष 2 अंक 107

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट में टेकऑफ से पहले आग, पायलट ने भेजा मेडे कॉल, 60 यात्रियों को सुरक्षित निकाला

24 न्यूज अपडेट

अहमदाबाद। बुधवार सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब इंडिगो की ATR 76 फ्लाइट के इंजन में टेकऑफ से ठीक पहले आग लग गई। यह विमान अहमदाबाद से दीव जाने वाला था और इसमें 60 यात्री सवार थे। सुबह लगभग 11 बजे रनवे पर टेकऑफ की प्रक्रिया शुरू ही हुई थी कि पायलट को इंजन में तकनीकी गड़बड़ी महसूस हुई। तुरंत स्थिति को भांपते हुए पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को इमरजेंसी 'मेडे' कॉल भेजा और विमान को रोका गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लगातार दूसरे दिन विमान में आग की घटना यह घटना ऐसे समय पर हुई जब इससे ठीक एक दिन पहले, मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर हॉन्गकॉन्ग से आई एयर इंडिया की फ्लाइट AI-315 के ऑक्सिलरी पावर यूनिट (APU) में लैंडिंग के तुरंत बाद आग लग गई थी। हालाँकि उस घटना में भी किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा था। APU विमान की टेल में स्थित होता है, और उसमें आग लगने से विमान की संरचना को गंभीर नुकसान हो सकता है। दोनों मामलों में विस्तृत जांच की प्रक्रिया जारी है।

'मेडे कॉल' क्या होता है?

'मेडे (Mayday)' शब्द फ्रेंच शब्द 'm'aider' से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है "Help Me" यानी "मुझे मदद चाहिए"। यह सिग्नल पायलट द्वारा रेडियो के माध्यम से ATC और आसपास के विमानों को आपात स्थिति में भेजा जाता है ताकि तत्काल प्राथमिकता और सहायता मिल सके। गौरतलब है कि इसी साल 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एक फ्लाइट क्रैश हो गई थी, जिसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी। क्रैश से ठीक पहले पायलट ने भी मेडे कॉल भेजा था, लेकिन सहायता समय पर नहीं पहुंच पाई। मंगलवार को ही एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में आई थी तकनीकी खराबी इसी मंगलवार को दिल्ली से कोलकाता जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2403 में भी टेकऑफ से ठीक पहले तकनीकी खराबी सामने आई थी। विमान उस समय 160 यात्रियों के साथ रनवे पर था और उड़ान भरने ही वाला था, लेकिन समस्या सामने आते ही उड़ान रोक दी गई।

गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का खुलासा: चार काल्पनिक देशों का बना 'राजदूत', 44 लाख कैश, 34 फर्जी मोहरें और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जब्त

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में मंगलवार को एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जब राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने कविनगर इलाके में संचालित एक फर्जी दूतावास पर छापेमारी कर एक हाई-प्रोफाइल जालसाज को गिरफ्तार किया। आरोपी हर्षवर्धन जैन खुद को 'वेस्ट आर्कटिक', 'सबोरगा', 'पुलावाविया' और 'लोडोनिया' जैसे काल्पनिक देशों का कॉन्सुल एंबेसडर बताता था। STF ने उसे उसके किराए के मकान से गिरफ्तार किया, जहां वह खुद को विदेशी राजनयिक साबित करने के लिए 'एम्बेसी ऑफ वेस्ट आर्कटिक' के नाम से फर्जी दूतावास चला रहा था।

छापेमारी के दौरान STF ने आरोपी के पास से 44.70 लाख नकद, 34 विभिन्न विदेशी कंपनियों व देशों की जाली मोहरें, विदेश मंत्रालय की फर्जी मुहर वाले दस्तावेज, 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, 2 फर्जी पैन कार्ड, 2 फर्जी प्रेस कार्ड, 18 वीआईपी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट और कई देशों की विदेशी मुद्रा जब्त की है। इसके अलावा चार लग्जरी गाड़ियाँ भी बरामद की गई हैं, जिन पर डिप्लोमेटिक झंडे और वीआईपी नंबर प्लेट लगी हुई थीं। STF के एसएसपी सुशील घुले ने बताया कि आरोपी हर्षवर्धन देश-विदेश में नौकरी दिलाने, कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का फर्जी लाइसेंस दिलाने और हवाला कारोबार में संलिप्त था। वह खुद को अत्यधिक प्रभावशाली और अंतरराष्ट्रीय स्तर का राजनयिक दर्शाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और अन्य शीर्ष नेताओं के साथ मॉर्फ की गई तस्वीरों का इस्तेमाल करता था। कई बार वह डिप्लोमेटिक गाड़ियों से सरकारी कार्यक्रमों में भी घुसने की कोशिश करता था।

सूत्रों के अनुसार, आरोपी हर्षवर्धन ने लंदन से एमबीए की पढ़ाई की है और उसका पहले का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। वर्ष 2011 में वह दक्षिण अफ्रीका से भारत में सैटेलाइट फोन लेकर आया था और सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों में आया था। बिना अनुमति के सैटेलाइट फोन ऑन करने के तुरंत बाद उसकी लोकेशन ट्रेस की गई और उसे दिल्ली में हिरासत में लिया गया। हालांकि, जांच में उसके खिलाफ कोई राष्ट्रविरोधी गतिविधि नहीं पाई गई थी, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया था। उस वक्त भी गाजियाबाद के कविनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।

हर्षवर्धन पूर्व में खुद को आध्यात्मिक गुरु चंद्रास्वामी और कुख्यात अंतरराष्ट्रीय हथियार डीलर अदनान खशोगी का करीबी भी बता चुका है। वह हाई-प्रोफाइल नेटवर्क का भ्रम फैलाकर लोगों को फंसाता था और विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी कर चुका है। वह विभिन्न फर्जी वेबसाइट्स, फर्जी माइक्रोनेशन प्रोजेक्ट्स और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जाल को फैलाता था।

गाजियाबाद का कविनगर इलाका, जहां यह फर्जी दूतावास संचालित हो रहा था, शहर का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। इसी क्षेत्र में पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय भी हैं। जिस घर में 'वेस्ट आर्कटिक दूतावास' का बोर्ड लगा था, उसके बाहर डिप्लोमेटिक झंडों से सजी गाड़ियाँ खड़ी थीं। यही नहीं, वहां 'अनूप सिंह' नाम की फर्जी नेमप्लेट भी लगी थी। करीब 100 मीटर दूर दूसरा मकान, जहां हर्षवर्धन का आना-जाना था, उसके पिता एचडी जैन के नाम पर है।

STF ने बताया कि इस फर्जीवाड़े की सूचना सबसे पहले केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से विदेश मंत्रालय तक पहुंची थी। मंत्रालय के निर्देश और जांच के बाद STF ने पूरी प्लानिंग के साथ कार्रवाई की। अब इस पूरे नेटवर्क की विस्तार से जांच की जा रही है और आरोपी के विदेशी संपर्कों तथा हवाला चैनलों की कड़ियों को खंगाला जा रहा है। उसे विभिन्न धाराओं में गाजियाबाद के कविनगर थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर जेल भेजा गया है।

भारत बनाम इंग्लैंड चौथा टेस्ट – जायसवाल का टूटा बल्ला, मजबूत शुरुआत, राहुल ने रचा इतिहास

24 न्यूज अपडेट

मैनचेस्टर | भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा और निर्णायक टेस्ट बुधवार से मैनचेस्टर में शुरू हुआ। मैच के पहले दिन भारत ने शानदार आगाज करते हुए पहले सत्र में बिना विकेट गंवाए 63 रन बना लिए। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल क्रीज पर डटे हुए हैं। दोनों के बीच 50 रन की सधी हुई साझेदारी हो चुकी है।

राहुल ने इंग्लैंड में पूरे किए 1000 रन, बने पांचवें भारतीय

भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने इस टेस्ट के दौरान एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने इंग्लैंड की धरती पर अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं और ऐसा करने वाले वे भारत के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर (1575 रन), राहुल द्रविड़ (1376 रन), सुनील गावस्कर (1152 रन) और विराट कोहली (1096 रन) यह मुकाम हासिल कर चुके हैं। जायसवाल का टूटा बल्ला, फिर भी लय में बल्लेबाजी मैच के शुरुआती ओवरों में एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। पांचवें ओवर में जब इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स ने गुड लेंथ डिलीवरी फेंकी, तो जायसवाल ने उसे बचावात्मक ढंग से खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले के हैंडल के पास लगी और

अचानक उनका बैट टूट गया। स्थिति इतनी अजीब थी कि उन्हें नया बैट मंगाना पड़ा, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना संयम नहीं खोया और ठोस बल्लेबाजी जारी रखी।

भारत ने लगातार 14वां टॉस गंवाया, फिर भी की सधी हुई शुरुआत

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने लगातार 14वां टॉस गंवा दिया, जिससे यह भारत का इस साल का सबसे लंबा टॉस हारने का सिलसिला बन गया है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनी, यह कहते हुए कि ओवरकास्ट कंडीशन गेंदबाजों के लिए मुफीद होंगी। गिल ने कहा कि वे निर्णय को लेकर असमंजस में थे, इसलिए टॉस हारना शायद बेहतर रहा।

नवागंतुक अंशुल कम्बोज का टेस्ट डेब्यू

भारतीय टीम में तीन अहम बदलाव हुए हैं। सबसे खास बात यह रही कि तेज गेंदबाज अंशुल कम्बोज को टेस्ट डेब्यू का मौका मिला। उन्हें पूर्व भारतीय विकेटकीपर दीप दासगुप्ता ने टेस्ट कैप पहनाई। इसके अलावा साई सुदर्शन और शार्दुल ठाकुर को भी अंतिम एकादश में शामिल किया गया है। करुण नायर, नीतीश रेड्डी और आकाश दीप को टीम से बाहर रखा गया है।

फारुख इंजीनियर और क्लाइव लॉयड ने किया मैच का उद्घाटन

चौथे टेस्ट का शुभारंभ भारत के पूर्व विकेटकीपर फारुख इंजीनियर और वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्लाइव लॉयड ने ओल्ड ट्रैफर्ड में बेल बजाकर किया। खास बात यह रही कि दोनों ही खिलाड़ियों के नाम पर लंकाशायर स्टेडियम में एक-एक स्टैंड का उद्घाटन भी हुआ।

पिच रिपोर्ट और मौसम की स्थिति

ओल्ड ट्रैफर्ड में मौसम फिलहाल साफ है और पहले दिन का खेल बिना किसी बाधा के शुरू हुआ। हालांकि, मौसम विभाग ने रात में बारिश की संभावना जताई है, जिससे आने वाले दिनों में मैच प्रभावित हो सकता है। पिच की सतह में गति और उछाल मौजूद है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिनरों को भी मदद मिलने की उम्मीद है।

भारत की प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अंशुल कम्बोज।

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: बेन स्टोक्स (कप्तान), जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, जैमी स्मिथ, लियम डॉसन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स।

चार दिनों में सोना-चांदी दोनों के भावों में दिखा उछाल, चांदी ने पकड़ी तेज रफ्तार

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 23 जुलाई। उदयपुर सर्राफा बाजार में पिछले चार दिनों के भीतर सोने और चांदी दोनों के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 16 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक की अवधि में चांदी के टंच भाव में करीब 6,250 प्रति किलो की बढ़त दर्ज की गई है, जबकि सोने के स्टैंडर्ड (999) भाव में 2,000 प्रति दस ग्राम तक का इज़ाफा हुआ है। 16 जुलाई को चांदी टंच का भाव 1,10,650 प्रति किलोग्राम था, जो 19 जुलाई को बढ़कर 1,13,300 हो गया। इसके बाद 21 जुलाई को यह 1,13,600 और 22 जुलाई को 1,14,300 पर पहुंचा। 23 जुलाई को चांदी के दामों ने और रफ्तार पकड़ते हुए 1,16,900 तक की ऊंचाई छू ली। इसी तरह चांदी चौरसा के भाव भी इसी प्रवृत्ति के साथ 16 जुलाई को 1,09,800 से बढ़कर 23 जुलाई को 1,16,000 तक पहुंच गए। वहीं, सोने की बात करें तो 16 जुलाई को स्टैंडर्ड (999) शुद्धता वाला सोना 98,500 प्रति दस ग्राम पर था, जो 19 जुलाई को 98,800 हुआ। 21 और 22 जुलाई को यह क्रमशः 99,500 और 99,600 तक पहुंचा। 23 जुलाई को सोना स्टैंडर्ड ने 1,00,500 का आंकड़ा छू लिया। इसी अवधि में 23 कैरेट जेवराती सोना 94,560 से बढ़कर 96,480 तक पहुंचा, जबकि 22 कैरेट सोना 90,620 से बढ़कर 92,460 प्रति दस ग्राम हो गया। इस चार दिवसीय अवधि में जहां चांदी की कीमतों में लगातार तेजी रही और कुल मिलाकर 5.6% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं सोने के भावों में भी लगभग 2% तक की बढ़त दर्ज हुई है। विश्लेषकों के अनुसार वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां, कच्चे तेल के उतार-चढ़ाव, डॉलर की स्थिति और आगामी त्योहारी सीजन की आहट इस मूल्यवृद्धि के पीछे प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशक वर्ग अब सुरक्षित निवेश के रूप में एक बार फिर से सोने-चांदी की ओर रुख कर रहा है, जिससे इनकी मांग में वृद्धि हो रही है। बाजार में चल रही इस तेजी को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी दिनों में भी यदि वैश्विक संकेत सकारात्मक रहे, तो सर्राफा बाजार में यह उछाल जारी रह सकता है।

सेंसेक्स 540 अंक चढ़कर 82,727 पर बंद:निफ्टी में 159 अंक की तेजी रही, NSE के मेटल-ऑटो इंडेक्स चढ़े, रियल्टी 3% टूटा

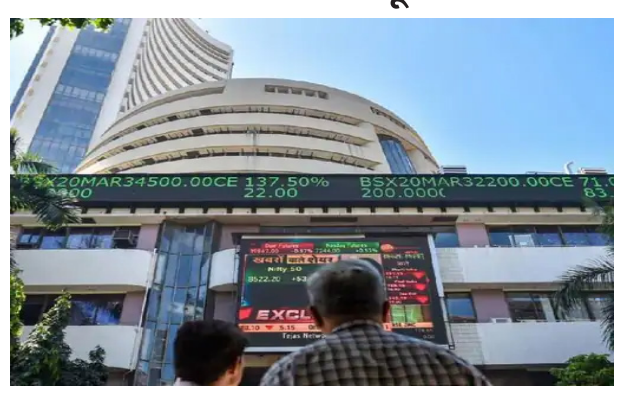

24 न्यूज अपडेट

हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार (23 जुलाई) को सेंसेक्स 540 अंक चढ़कर 82,727 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 159 अंक की तेजी रही, ये 25,220 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट रही। टाटा मोटर्स, एयरटेल और बजाज फाइनेंस के शेयर 2.55% तक चढ़े। HUL, इंफोसिस और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर्स गिरकर बंद हुए। निफ्टी के 50 शेयरों में से 39 में तेजी और 11 में गिरावट है। NSE का निफ्टी मेटल, ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और फार्मा इंडेक्स चढ़कर बंद हुए। रियल्टी इंडेक्स करीब 3% नीचे आ गया।

ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में होगी चर्चा: लोकसभा में 28, राज्यसभा में 29 जुलाई को होगी 16-16 घंटे की बहस

24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर संसद का मानसून सत्र लगातार तीसरे दिन भी बाधित रहा। विपक्षी दलों के तीखे विरोध और नारेबाजी के चलते बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कुछ ही मिनटों में स्थगित कर दी गई। इस बीच सरकार ने इन मुद्दों पर गंभीर बहस की घोषणा करते हुए बताया कि लोकसभा में 28 जुलाई और राज्यसभा में 29 जुलाई को 16-16 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है।

संपादकीय : भुखमरी का दायरा

दुनिया भर में विकास के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। बुनियादी ढांचे से लेकर प्रौद्योगिकी के विकास में नई-नई मिसाल कायम की जा रही हैं। इसी का दंभ भरकर किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज करने या फिर भविष्य में चांद पर बस्ती बसाने के दावे भी किए जा रहे हैं। मगर, क्या वास्तव में विकास का पैमाना यही है? समाज के समग्र उत्थान का तत्त्व विकास की इस धारा में कहां है ? यह कै सा विकास है कि एक तरफ विभिन्न देश तकनीक के बूते खुद के ताकतवर एवं साधन संपन्न होने का राग अलाप रहे हैं, तो दूसरी ओर दुनिया में करोड़ों लोग भुखमरी के कारण अपने शरीर की ताकत भी खो रहे हैं । विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन की 'वैश्विक खाद्य संकट' पर एक हालिया रपट में किए गए खुलासे चिंताजनक है। इसमें कहा गया है कि दुनिया भर में उनतीस करोड़ से अधिक लोग ऐसे हालात में जी रहे हैं, जहां उनके लिए एक वक्त का भोजन जुटा पाना भी मुश्किल है। साफ है कि समाज का सबसे कमजोर तबका आज भी संघर्ष, महंगाई, प्राकृतिक आपदा और जबरन विस्थापन जैसी समस्याओं के चक्रव्यूह में उलझा हुआ है। संसाधनों के अभाव और संकटग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की डगर ज्यादा कठिन हो गई है। रपट में सामने आया है कि 2024 में लगातार छठे वर्ष दुनिया में गंभीर खाद्य संकट और बच्चों में कुपोषण बढ़ा है। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्ष 53 देशों या क्षेत्रों के 29.5 करोड़ लोग गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे थे । यह आंकड़ा वर्ष 2023 के मुकाबले 1.37 करोड़ अधिक है। यानी सुधार के बजाय स्थिति पहले से कहीं अधिक खराब हो गई है। भुखमरी के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें दो देशों के बीच युद्ध और आंतरिक संघर्ष प्रमुख हैं। इन दो कारणों से ही बीस देशों में करीब 14 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हैं। जाहिर है, अंतरराष्ट्रीय संघर्षों की वजह से हालात और ज्यादा बदतर हो रहे हैं । युद्ध के दौरान प्रभावित लोगों को राहत के तौर पर खाद्य सामग्री पहुंचाने पर रोक लगा देने की खबरें भी आती रहती हैं। इस तरह के प्रयास वास्तव में मानवीय संवेदनाओं के दम तोड़ देने की ओर इशारा करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी से उपनी विकट आर्थिक स्थितियां भी भुखमरी के लिए जिम्मेदार हैं। रपट में कहा गया है कि इन दोनों कारणों से पंद्रह देशों में 5.94 करोड़ लोगों का जीवन संकट में है। इसके अलावा, सुखा और बाढ़ ने 18 देशों में 9.6 करोड़ लोगों को खाद्य संकट में धकेल दिया है। इस पर तुर्रा यह है कि इन लोगों को खाद्य एवं पोषण सहायता के लिए मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मदद में भी भारी गिरावट आई है। ऐसा लगता है कि वैश्विक मदद और राजनीतिक इच्छाशक्ति की सांसें धीरे-धीरे उखड़ रही हैं। ऐसे में जबरन विस्थापन भुखमरी के संकट को और बढ़ा रहा है। 21वीं सदी में भी अगर भुखमरी की समस्या विकराल होती जा रही है, तो यह व्यवस्था के साथ-साथ मानवता के लिए भी खतरे की घंटी है । इस समस्या से निपटने के लिए जरूरी है कि संकटग्रस्त इलाकों में स्थानीय खाद्य प्रणालियों और पोषण सेवाओं में निवेश पर जोर दिया जाए। समय आ गया है कि विभिन्न देशों की सरकारें जनकल्याण की योजनाओं की व्यापक समीक्षा करें और भुखमरी को दूर करने के लिए उचित एवं प्रभावी उपाय किए जाएं। खाली पेट के सवाल का जवाब खाली हाथों और पीठ फेरकर नहीं दिया जा सकता।

बुजुर्गों की फिक्र

हमारे देश में परिवार और समाज की जैसी परंपरा रही है, उसमें कई बार ऐसी बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि कोई संतान ही अपने माता-पिता की न सिर्फ संवेदनात्मक जरूरतों, बल्कि अधिकारों तक से वंचित करने की कोशिश करने लगती है। ऐसे में सरकार और अन्य संबंधित महकमों का दखल जरूरी होता है, ताकि एक नागरिक के रूप में बुजुर्गों के अधिकारों का हनन रोका जा सके। इस लिहाज से देखें, वे हरिवण मानवधिकार आयोग ने उचित ही एक बुजुर्ग दंपति के पक्ष में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों से भरण-पोषण का दावा करने के हकदार हैं और धारा-23 के तहत देखभाल की शर्त पर हस्तांतरित की गई किसी भी संपत्ति को देखभाल नहीं किए जाने की स्थिति में अमान्य घोषित किया सकता है। साथ ही, धारा- 24 के तहत वरिष्ठ नागरिक को त्याग देना दंडनीय अपराध है। गौरतलब है कि हरियाणा के पंचकूला में अपने बेटे और बहू के साथ एक घर में रहने के बावजूद एक बुजुर्ग दंपति को अलग-थलग रखा गया, उन्हें अपशब्द कहे गए, उनकी आवासीय संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए दबाव डाला गया, झूठा मामला दर्ज कराया गया और उनसे वृद्धाश्रम तक चले जाने को कहा गया। समाज जैसे- जैसे आधुनिक होता जा रहा है, उसमें उम्मीद इस बात की भी थी कि वह मानवीय मूल्यों को भी समृद्ध करेगा। मगर वक्त के साथ हुआ यह है कि माता-पिता के त्याग की नींव पर सभी तरह की सुख-सुविधाएं हासिल करने वाली नई पीढ़ी मां-पिता का न्यूनतम खयाल रखना भी जरूरी नहीं समझती। दूसरी ओर, परिवारों में कई स्तर पर उपेक्षा झेलने वाले बुजुगों के लिए ऐसे वृद्धाश्रम भी गिनती के हैं, जहां वे कम से कम संतोषजनक तरीके से अपना बचा जीवन काट सकें। यह एक अफसोसनाक तस्वीर है कि माता-पिता अपने जिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अपनी जिंदगी झोंक देते हैं, उनके सुख के लिए अपने जीवन की न्यूनतम सुविधाओं तक को छोड़ देते हैं, वे बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय कई बार उनके लिए दुख का कारण बन जाते हैं।

उदयपुर में भी महंगी हुई हाउसिंग बोर्ड की जमीनें: गोवर्धन विलास की दरों में 9% तक इजाफा, अब 23,190 रु./वर्गमीटर

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने प्रदेशभर की कॉलोनियों की जमीनों की आरक्षित दरों (रिजर्व प्राइस) में बड़ा बदलाव करते हुए 8% से लेकर 44% तक की बढ़ोतरी कर दी है। जयपुर में जहां सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं उदयपुर में भी गोवर्धन विलास योजना और एक्सटेंशन स्कीम की दरें 21,370 रुपए प्रति वर्गमीटर से बढ़कर अब 23,190 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दी गई हैं। यह करीब 8.5% से अधिक की बढ़ोतरी मानी जा रही है।

निवेश और खरीदारी पर असर की संभावना

हाउसिंग बोर्ड की इस वृद्धि का असर उदयपुर में जमीन खरीदने की योजना बना रहे आम लोगों, मध्यम वर्ग और निवेशकों पर पड़ेगा। गोवर्धन विलास क्षेत्र, जो हाउसिंग बोर्ड की प्रमुख योजनाओं में से एक है, वहां अब जमीन खरीदना पहले की तुलना में और महंगा हो गया है। एक्सटेंशन योजना में भी यही दर लागू की गई है, जिससे नए प्लॉट खरीदने वालों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। राज्यभर में जयपुर में सर्वाधिक वृद्धि जयपुर में सबसे ज्यादा वृद्धि वाटिका स्कीम में देखी गई है, जहां दर 4,890 रुपए से बढ़ाकर सीधे 7,045 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दी गई है — यानी करीब 44% की बढ़ोतरी। मानसरोवर, प्रताप नगर और अजमेर रोड महला योजना में भी 22% से 35% तक की वृद्धि की गई है। उदयपुर के अलावा, जोधपुर की बड़ली आवासीय योजना, कुड़ी भगतासनी और चौपासनी योजना, अलवर की बी-10 योजना, भिवाड़ी की अरावली विहार, और अजमेर की किशनगढ़ योजना की दरों में भी 8% से 9% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

उदयपुरवासियों के लिए क्या मायने रखती है यह बढ़ोतरी?

मकान बनाने की लागत बढ़ेगी: प्लॉट महंगे होने से मकान की कुल लागत पर असर पड़ेगा।

मध्यम वर्ग के लिए चुनौती: जिन लोगों ने हाउसिंग बोर्ड के जरिए घर खरीदने की योजना बनाई थी, उनके बजट पर असर पड़ेगा।

निवेश के दृष्टिकोण से मिला संकेत: हाउसिंग बोर्ड की दरों में बढ़ोतरी से यह भी संकेत मिलता है कि राज्य सरकार को इन क्षेत्रों में भूमि की मांग और कीमत में वृद्धि की उम्मीद है।

विशेषज्ञों की राय- स्थानीय रियल एस्टेट सलाहकारों के अनुसार, गोवर्धन विलास क्षेत्र पहले ही विकसित हो रहा है और इसमें कई निजी टाउनशिप, स्कूल, कॉलेज और कमर्शियल स्पॉट विकसित हो चुके हैं। ऐसे में भूमि दरों में बढ़ोतरी बाजार की मांग और लोकेशन वैल्यू को देखते हुए अपेक्षित थी, लेकिन अचानक 9% तक की बढ़ोतरी ने कई संभावित खरीदारों को असमंजस में डाल दिया है।

सांवलियाजी के दानपात्र से पहले दिन निकले 7.15 करोड़ रुपए:अगली गिनती 25 को होगी, अमावस्या पर नहीं होगी गणना

24 न्यूज अपडेट

मेवाड़ के कृष्णधाम भगवान श्री सांवलिया सेठ जी के मंदिर में बुधवार को दान पात्र खोला गया। यह दान पात्र हर महीने खोला जाता है, ताकि उसमें जमा हुई राशि की गिनती की जा सके। इस बार पहले ही दिन, सात करोड़ 15 लाख रुपयों की गिनती हुई है।

दान पात्र चतुर्दशी की सुबह राजभोग आरती के बाद खोला गया। जैसे ही भंडार खोला गया, भक्तों ने "जय सांवरा सेठ" के जोरदार नारे लगाए। माहौल भक्तिमय हो गया था। मंदिर मंडल के सभी सदस्य और अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे।

नोटों की गिनती मंदिर मंडल के कर्मचारी और बैंक के स्टाफ द्वारा मिलकर की गई। सुबह से शुरू हुई गिनती शाम तक चली, जिसमें लाखों की संख्या में नोटों को सावधानी से निकाला गया, गिना गया और फिर रिकॉर्ड किया गया। 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या है। इस दिन मंदिर में भीड़ रहती है, इसलिए सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गिनती नहीं की जाएगी। अब अगली गिनती 25 जुलाई को होगी।

मंदिर के अधिकारियों के अनुसार यह केवल पहला दिन है। आने वाले दिनों में दान पात्र के साथ-साथ भेंट कक्ष में मिले गहनों, चांदी, सोने और ऑनलाइन ट्रांसफर हुए दान की भी गणना की जाएगी। साथ ही जो भक्त सीधे मंदिर आकर नकद भेंट देते हैं, उसकी भी अलग से गिनती की जाएगी। सांवलिया सेठ जी को धन-दौलत और व्यापार में वृद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। देशभर से लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं और दिल खोलकर दान करते हैं।

वल्लभनगर में शीतला माता मंदिर में श्रद्धाभाव से झाला ने चढ़ाए सवा चार किलो आभूषण, 1 जुलाई को 30 किलो चांदी के आभूषण हो गए थे चोरी

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, उदयपुर। उदयपुर जिले के वल्लभनगर स्थित ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर में मंगलवार को श्रद्धा और भक्ति का अद्वितीय संगम देखने को मिला। भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रभारी हिम्मत सिंह झाला ने माता को सवा चार किलो चांदी के आभूषण और भव्य पोशाक अर्पित की। यह सेवा उन्होंने अपने माता-पिता की श्रद्धा और भावना के अनुरूप की। इस मौके पर नगर में भक्ति उल्लास से भरी शोभायात्रा निकाली गई, जो डांगी चौराहे से शुरू होकर भक्ति गीतों, जयकारों और नृत्य की गूंज के बीच मंदिर तक पहुंची। महिलाओं और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या ने उत्साह से सहभागिता की। मंदिर पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना कर माता का विशेष श्रृंगार किया गया।

कार्यक्रम के दौरान हिम्मत सिंह झाला ने मंदिर में हुई चोरी की घटना को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई में विफल रहने का आरोप लगाते हुए चोरों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि आस्था के केंद्र पर इस तरह की घटनाएं न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती हैं, बल्कि जनभावनाओं को भी आहत करती हैं। गौरतलब है कि 1 जुलाई को इसी मंदिर से लगभग 30 किलो चांदी के कीमती आभूषण चोरी हो गए थे, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। चोरी के विरोध में कांग्रेस भी पूर्व में प्रदर्शन कर चुकी है। इस श्रद्धामय आयोजन में क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि, समाजजन और श्रद्धालु उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय निगम योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुरू

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 23 जुलाई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय निगम की योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुरू कर दिया गया है। इसके माध्यम से राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित विभिन्न राष्ट्रीय निगम योजनाओं के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। इस पोर्टल के जरिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एवं राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

अनुजा निगम सहायक परियोजना प्रभारी वीना मेहरचंदानी ने बताया कि आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन के लिए आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है। इसके तहत लघु व्यवसाय (शहरी एवं ग्रामीण), महिला समृद्धि योजना, डेयरी, ई-रिक्शा आदि योजनाओं के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदक स्वयं एसएसओ आईडी के माध्यम से या ई-मित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा किसी अन्य ऋणदात्री संस्था से ऋणी नहीं होने की स्वयं घोषणा को स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।

फिल्मी अंदाज़ में शटर फाड़ चोरी, डीजी टेक शॉप से लाखों का माल साफ, चोरों ने पड़ोसी दुकान की दीवार तोड़ बनाई सेंध, CCTV नहीं था दुकान में

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। शहर के सूरजपोल क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक हाईटेक चोरी की वारदात सामने आई, जहां अज्ञात चोरों ने फिल्मी स्टाइल में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये का सामान उड़ा लिया। चोरी का खुलासा बुधवार सुबह दुकान खुलने पर हुआ, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, चोरी की यह वारदात सूरजपोल से उदियापोल जाने वाली रोड पर स्थित 'डीजी टेक' इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में हुई। चोरों ने पहले दुकान के पास वाली एक शॉप की टीनशेड को तोड़ा, फिर उसके जरिए अंदर घुसकर डीजी टेक शॉप की दीवार में बड़ा छेद कर भीतर दाखिल हो गए। चोर दुकान से सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान समेट कर फरार हो गए। अनुमान है कि चोरी गए माल की कीमत लाखों में है।

पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची

घटना की जानकारी मिलते ही सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। चोरी की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और मौके का बारीकी से निरीक्षण किया।

CCTV नहीं, सुराग की तलाश में जुटी पुलिस

चोरी की शॉप में CCTV कैमरा नहीं लगा था, जिससे आरोपियों की पहचान में मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि पुलिस ने आसपास के अन्य दुकानों और क्षेत्रों के कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं, ताकि चोरों की कोई तस्वीर या सुराग मिल सके। फिलहाल सूरजपोल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मेवाड़ जनशक्ति दल के सदस्यों ने किया पौधारोपण

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर 23 जुलाई। मेवाड़ जनशक्ति दल के सदस्यों की ओर से एक पेड़ मां के नाम थीम पर पौधारोपण किया गया। संस्थापक नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि मेवाड़ जनशक्ति दल फलासिया अध्यक्ष डॉ हेमेंद्र सिंह शक्तावत एवं टीम ने कई सेवा कार्य किये गए। जिसमे उदयपुर अपना घर आश्रम में सभी निराश्रितों को भोजन कराया और सभी सदस्यों ने एक एक पौधा लगाने का संकल्प लिया शाम को श्रीराम बजरंग सेवा समिति द्वारा सुंदरकांड का पाठ कर किया। मेवाड़ जनशक्ति दल संस्थापक नरेश कुमार शर्मा, भाजपा मण्डल अध्यक्ष भोपाल सिंह शक्तावत, ओबीसी मण्डल लक्ष्मी लाल लोहार, नारायण पुजारी, मोहन निनामा, उपाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, दीपक वैरागी, चतर सिंह, बसंती लाल, दीपक संसावत, ईश्वर सिंह, राहुल, कमलेश, हरीश सहित सभी संगठन के कई सदस्य उपस्थित रहे।

मोदी केमिकल फैक्ट्री पर सामान डिलीवर करने आए ड्राइवर की हाईटेंशन लाइन से चिपक कर मौत, कल की घटना, आज दबाव बढ़ने व सीसीटीवी आने पर परिजनों को पता चला सच, फैक्ट्री बाहर हंगामा

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 23 जुलाई। डबोक थाना क्षेत्र स्थित रीको एरिया में मंगलवार दोपहर मोदी केमिकल फैक्ट्री पर एक दर्दनाक हादसे में ट्रक ड्राइवर की करंट लगने से मौत हो गई। 40 वर्षीय रामलाल गाडरी फैक्ट्री में सामान डिलीवर करने आया था। सामान उतारने के बाद वह ट्रक पर तिरपाल ठीक कर रहा था, तभी ऊपर से गुजर रही 11000 केवी की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। केवल दो सेकंड में ही वह ट्रक पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई।

फैक्ट्री प्रशासन ने छिपाई सच्चाई, CCTV आने पर खुला राज

हादसे के तुरंत बाद फैक्ट्री प्रशासन ने परिजनों को सूचना तो दी, लेकिन मौत के सही कारण नहीं बताए। जब परिजन एमबी अस्पताल पहुंचे, तो वहां भी उन्हें करंट लगने की बात नहीं बताई गई। बुधवार को जब घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया और स्थानीय समाजजनों ने दबाव बनाया, तब जाकर वास्तविकता का पता चला। इसके बाद परिजनों और समाज के लोगों ने फैक्ट्री के बाहर धरना शुरू कर दिया। फैक्ट्री के सामने धरना, महिलाओं की भी मौजूदगी नूरड़ा सरपंच मनोहरलाल गुर्जर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग मोदी केमिकल फैक्ट्री के बाहर जुटे और टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। वे फैक्ट्री मालिक को मौके पर बुलाकर उचित मुआवजा देने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धरने में महिलाओं की भी भागीदारी रही। स्थिति को देखते हुए डबोक, फतहनगर और घासा थाना पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। प्रशासन की समझाइश, लेकिन परिजन अडिग घटना स्थल पर एसडीएम रमेश सिरवी, पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंचे। मावली विधायक पुष्करलाल डांगी, मावली प्रधान नरेंद्र जैन, भाजपा नेता कुलदीप सिंह चुंडावत भी धरना स्थल पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। परिजन तब तक धरने से हटने को तैयार नहीं हैं जब तक फैक्ट्री मालिक मुआवजा देने और बिजली विभाग की लापरवाही की जिम्मेदारी तय करने का आश्वासन नहीं देता।

बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल

डबोक थानाधिकारी हुकम सिंह ने बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन ने पहले ही बिजली विभाग को 11000 केवी लाइन को ऊंचा उठाने या हटाने के लिए शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह लापरवाही अब जानलेवा साबित हुई है।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

रामलाल गाडरी अपने पूरे परिवार का एकमात्र सहारा था। उसके दो बच्चे हैं – 15 साल का बेटा और 9 साल की बेटी। अब इस हादसे के बाद पूरे परिवार की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। समाजजन इस हादसे को लेकर बेहद आक्रोशित हैं।

बिहार को रेलवे क्षेत्र में ऐतिहासिक बढ़तः 11 वर्षों में 9 गुना बजटीय उछाल, शिवहर-सीतामढ़ी परियोजना को मिली रफ्तार

24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में बिहार में चल रही रेलवे परियोजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य को रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि 11 वर्ष पूर्व बिहार के लिए रेलवे बजट मात्र 1132 करोड़ था, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दिया है। यह नौ गुना वृद्धि राज्य की आकांक्षाओं और जरूरतों के प्रति केंद्र सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, "इन परियोजनाओं की शुरुआत भी एनडीए सरकार ने की थी और समापन भी एनडीए सरकार कर रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि बिहार की जनता के साथ न्याय केवल एनडीए ही कर सकती है।"

शिवहर–सीतामढ़ी रेल परियोजना को मिली गति, बागमती पर ब्रिज का टेंडर जारी

श्री वैष्णव ने शिवहर–सीतामढ़ी रेलवे परियोजना पर विस्तार से बोलते हुए बताया कि यह परियोजना राज्य के उत्तर-मध्य क्षेत्र की लाइफलाइन बनने जा रही है। इस परियोजना के तहत बागमती नदी पर एक नया पुल बनाया जाएगा, जो देकुली धाम शिवहर को रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। इस पुल के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। परियोजना के भूमि अधिग्रहण हेतु 262 करोड़ की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है और कार्य प्रगति पर है। साथ ही, सीतामढ़ी–शिवहर नई रेल लाइन परियोजना के लिए 557 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं और कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अमृत भारत ट्रेनों से गरीबों को नई सुविधा, बिहार को नई कनेक्टिविटी रेल मंत्री ने "अमृत भारत ट्रेनों" को गरीबों की सुविधा का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये ट्रेनें प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का परिणाम हैं, जिसका उद्देश्य है – सामान्य नागरिकों को भी आधुनिक रेल सुविधा उपलब्ध कराना।

बिहार को मिली मुख्य अमृत भारत ट्रेन कनेक्टिविटीः

पटना–दिल्ली
दरभंगा–दिल्ली
दरभंगा–बैंगलोर

श्री वैष्णव ने कहा कि इन ट्रेनों के जरिये बिहार के सामान्य यात्रियों को तेज, सुरक्षित और बेहतर यात्रा अनुभव प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य के और क्षेत्रों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। रेलवे विकास की नई परिभाषा लिख रहा बिहार कुल मिलाकर, बिहार के लिए रेलवे बजट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी और बड़े स्तर पर परियोजनाओं की घोषणा इस बात का प्रमाण है कि राज्य में सुधार, सुविधा और संरचना को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। रेलवे के माध्यम से बिहार के सामाजिक-आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है।

जजों पर टिप्पणी मामले में विकास दिव्यकीर्ति को हाईकोर्ट से राहत, अग्रिम कार्रवाई पर अंतरिम रोक, राज्य सरकार को पक्षकार बनाते हुए जवाब के लिए 2 सप्ताह का समय

24 न्यूज अपडेट

जयपुर। ज्यूडिशियरी पर की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज मामले में दृष्टि IAS कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्यकीर्ति को राजस्थान हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने मामले में अग्रिम कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया है। दिव्यकीर्ति की ओर से पेश हुए अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था और जिस वीडियो का हवाला दिया गया है, उसे तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि निचली अदालत द्वारा की गई आपराधिक कार्यवाही स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है और समुचित कानूनी प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया।

शिकायतकर्ता ने मानहानि का आरोप लगाया

मामले में शिकायतकर्ता कमलेश मंडोलिया की ओर से वकील राजेश कुमार शर्मा ने हाईकोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि दिव्यकीर्ति ने न्यायपालिका के विरुद्ध अपमानजनक और व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है, जिससे न्यायिक अधिकारियों की मानहानि हुई है। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने संपूर्ण प्रक्रिया कानून सम्मत तरीके से पूरी की है।

कोर्ट ने दिया जवाब देने का समय

शिकायतकर्ता मंडोलिया ने याचिका के जवाब के लिए कोर्ट से समय मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पक्षकार बनाते हुए सभी प्रतिवादियों को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अजमेर कोर्ट में पेश होने के दिए थे आदेश

इससे पहले कमलेश मंडोलिया की शिकायत पर अजमेर न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 के पीठासीन अधिकारी मनमोहन चंदेल ने दिव्यकीर्ति को 22 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए थे। याचिका पर समय पर सुनवाई नहीं होने के कारण दिव्यकीर्ति ने हाजिरी माफी की अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 2 अगस्त को पेश होने का आदेश जारी किया।

वीडियो से उपजा विवाद

पूरा मामला 'IAS वर्सेज जजः कौन ज्यादा ताकतवर' नामक वीडियो से शुरू हुआ, जिसमें दिव्यकीर्ति ने IAS को न्यायपालिका से अधिक शक्तिशाली बताया था। इस पर मंडोलिया ने मानहानि का दावा करते हुए कोर्ट का रुख किया था। मामले की बहस के बाद कोर्ट ने अपने 40 पेज के आदेश में शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिव्यकीर्ति को समन जारी किया था।

छात्रसंघ चुनाव की बहाली की मांग तेज़, यूनिवर्सिटी परिसर में छात्र नेता ने तोड़ा ताला

24 न्यूज अपडेट

जयपुर। राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव की बहाली को लेकर छात्र संगठनों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। बुधवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी में आक्रोशित छात्रों ने छात्रसंघ कार्यालय का ताला तोड़कर प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द चुनाव बहाल नहीं किए गए, तो प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा। छात्र नेता देव पलसानिया ने छात्रसंघ कार्यालय में ताला तोड़ने की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, "यह कार्यालय पिछले तीन वर्षों से आम छात्रों के लिए बंद पड़ा है, जबकि यहां से छात्रों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए था। प्रशासन ने इसे बंद कर रखा था, इसलिए हमने ताला तोड़ा है।" उन्होंने मांग की कि सरकार छात्रसंघ कार्यालय को दोबारा आम छात्रों के लिए खोले और चुनाव की प्रक्रिया तुरंत बहाल करे। पलसानिया ने आगे कहा, "यह विरोध केवल मेरा नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान के छात्रों का है। छात्रसंघ चुनाव लोकतंत्र की पहली सीढ़ी हैं और इन्हें बंद करना छात्रों के अधिकारों का हनन है।"

तीन साल से बंद हैं छात्रसंघ चुनाव

राजस्थान में पिछले तीन वर्षों से छात्रसंघ चुनाव स्थगित हैं, जिनकी बहाली को लेकर छात्रों में गहरा आक्रोश है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले एक महीने से लगातार विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने पूर्व छात्रसंघ पदाधिकारियों के कटआउट के साथ रैली निकाली थी। NSUI ने विरोध में 'लोकतंत्र की विदाई' का आयोजन कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बारात निकाली थी। वहीं, ABVP ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतीकात्मक अंतिम यात्रा निकालकर चुनाव बहाली की मांग दोहराई थी। अब तक सरकार का कोई स्पष्ट रुख नहीं छात्रों के लगातार विरोध और प्रदर्शन के बावजूद सरकार की ओर से छात्रसंघ चुनाव को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसी कारण से छात्र संगठनों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और वे अब प्रणालीगत आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं।

रेलवे ट्रेनों में महंगा पानी, खराब खाना और घटिया कपों पर कार्रवाई : IRCTC ने 23 ट्रेनों में पकड़े फर्जी ब्रांड, जब्त किए 100 से ज्यादा बॉक्स, जुर्माना प्रस्तावित

24 न्यूज अपडेट

जयपुर। रेलवे ट्रेनों में यात्रियों को ठंडा नाश्ता, घटिया गुणवत्ता वाले कप और अधिक दामों पर बिकती पानी की बोतलों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आईआरसीटीसी ने "शुद्ध के लिए युद्ध" अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 21 व 22 जुलाई को जयपुर, अजमेर और जोधपुर मंडलों की 23 ट्रेनों में औचक जांच कर अनाधिकृत ब्रांड के खाद्य और पेय पदार्थ जब्त किए गए। 15 की बोतल 20 में, लोकल ब्रांड की भरमार जांच में पाया गया कि कई ट्रेनों में अधिकृत ब्रांड 'रेलनीर' की बजाय लोकल और बिना अनुमति वाले ब्रांड्स की पानी की बोतलें यात्रियों को 15 की जगह 20 रुपये में बेची जा रही थीं। सबसे ज्यादा शिकायतें अरावली एक्सप्रेस (14702), उदयपुर सिटी एक्सप्रेस (19610), बाड़मेर-गुवाहाटी एक्सप्रेस (15631) और रानीखेत एक्सप्रेस (15013/15014) से आईं। जयपुर-पुणे एक्सप्रेस (12940) में श्रीकृष्णा ब्रांड की 50 बटर मिल्क की बोतलें और एक्वा ब्रांड का लोकल पानी जब्त किया गया। दयोदय एक्सप्रेस (12181) में M/s फूड वार्ड के वेंडर विजय के पास से गोल्डी ब्रांड का पानी मिला। रानीखेत एक्सप्रेस में KSI एसोसिएट्स के मैनेजर अर्जुन सिंह से बिसलरी ब्रांड के 13 बॉक्स जब्त किए गए। आला हजरत एक्सप्रेस (14311/14322) में भी अनअथॉराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स पाए गए। घटिया गुणवत्ता, खराब कप – वंदे भारत भी चपेट में वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को दिए जा रहे चाय के कप बेहद हल्की क्वालिटी के पाए गए जो लीक कर रहे थे। जबकि इस प्रीमियम ट्रेन में हार्ड कप का उपयोग अनिवार्य है। इस लापरवाही पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ जुर्माना लगाने की अनुशंसा की गई है। यात्रियों की शिकायतों से शुरू हुआ एक्शन IRCTC के महाप्रबंधक मुकेश सैनी के अनुसार, "1 से 20 जुलाई तक हमें 'रेल मदद' ऐप और ट्विटर पर सैकड़ों शिकायतें मिलीं। प्रमुख शिकायतें थीं

तय रेट से अधिक पैसा वसूलना
बिना अनुमति वाले पानी व खाद्य उत्पादों की बिक्री
खाने की गुणवत्ता में कमी
अवैध वेंडिंग"

इन्हीं शिकायतों के आधार पर 21 जुलाई से विशेष जांच अभियान शुरू किया गया। महज दो दिन में ही 23 ट्रेनों में बड़ी मात्रा में अवैध सामान पकड़ा गया और संबंधित वेंडरों पर जुर्माना लगाने की संस्तुति की गई। कुछ मामलों में जुर्माना राशि 25 हजार रुपये से अधिक प्रस्तावित है।

बेस किचन और नाश्ते पर भी नजर

जयपुर बेस किचन में सुबह 5 बजे जांच की गई। नाश्ता गर्म न होने की शिकायत सही पाई गई क्योंकि हीटिंग इक्विपमेंट ठीक से काम नहीं कर रहे थे। कुछ किचनों में एग्जॉस्ट सिस्टम भी खराब पाया गया जिसे तुरंत सुधारा गया। इस पूरे अभियान में रेलवे के मेडिकल विभाग से फूड सेफ्टी ऑफिसर भी शामिल किए गए हैं। जयपुर, जोधपुर और अजमेर के सभी लाइसेंस प्राप्त किचनों से फूड प्रोडक्ट्स के सैंपल लेकर लैब जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अभियान 30 जुलाई तक चलेगा

IRCTC का यह अभियान 30 जुलाई तक चलेगा। चारों रेलवे मंडलों – जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर – के DCM इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। जयपुर DCM खुद भी ट्रेनों में चेकिंग कर रहे हैं। रोजाना की कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार की जा रही है और यात्रियों के फीडबैक के आधार पर ट्रेनों और इलाकों की निगरानी बढ़ाई गई है।

राजस्थान हाईकोर्ट में ऐतिहासिक न्यायिक विस्तारः पहली बार 43 न्यायाधीश कार्यरत, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण की उम्मीद

24 न्यूज अपडेट

जोधपुर, 23 जुलाई। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक को साक्षी बनाया, जब सात नव नियुक्त न्यायाधीशों ने जोधपुर मुख्य पीठ में आयोजित समारोह में पद की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह शपथ ग्रहण केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं था, बल्कि न्यायिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक भी बना। इन नियुक्तियों के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या अब तक के सर्वोच्च आंकड़े 43 तक पहुंच गई है। नव नियुक्त न्यायाधीशों में जस्टिस संदीप तनेजा, जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू, जस्टिस बिपिन गुप्ता, जस्टिस संजीत पुरोहित, जस्टिस रवि चिरानिया, जस्टिस अनुरूप सिंघी और जस्टिस संगीता शर्मा शामिल हैं। इनमें से छह अधिवक्ता कोटे से और एक न्यायिक सेवा से नियुक्त हुए हैं। इन नियुक्तियों के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट देश के उन गिने-चुने उच्च न्यायालयों में शामिल हो गया है, जहां दो न्यायाधीश दंपत्ति कार्यरत हैं—जो अपने आप में एक अनोखा कीर्तिमान है।

वर्ष 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों की गति उल्लेखनीय रही है। जनवरी में तीन और मार्च में चार नियुक्तियों के बाद अब जुलाई में सात नए न्यायाधीशों के शामिल होने से इस साल कुल 15 नियुक्तियां हो चुकी हैं, जो एक कैलेंडर वर्ष में अब तक की सबसे अधिक हैं। यह नियुक्ति प्रक्रिया न केवल न्यायिक क्षमता को बढ़ाने वाली है, बल्कि न्यायिक प्रशासन के प्रति सरकार और उच्चतम न्यायपालिका की सक्रियता का भी संकेत देती है। उच्च न्यायालय की स्थापना के समय वर्ष 1949 में जब 11 न्यायाधीशों ने शपथ ली थी, तब से लेकर अब तक का यह सफर कई उतार-चढ़ावों से भरा रहा है। संविधान लागू होने के बाद न्यायाधीशों की संख्या घटकर छह रह गई थी। वर्ष 2018 में स्वीकृत पदों की संख्या को 36 से बढ़ाकर 50 किया गया, जिसके बाद जुलाई 2023 तक 41 न्यायाधीश कार्यरत थे। अब, ताजा नियुक्तियों के साथ यह संख्या पहली बार 43 तक पहुंची है।

न्यायाधीशों की बढ़ती संख्या का प्रत्यक्ष संबंध उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के तेजी से निस्तारण से जुड़ा हुआ है। 31 दिसंबर 2024 तक के उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान हाईकोर्ट में कुल 6,82,946 प्रकरण लंबित थे। इनमें 1,64,450 दीवानी, 1,86,806 फौजदारी और 3,31,690 रिट याचिकाएं थीं। जोधपुर और जयपुर पीठों में विभाजित इन मामलों में सर्वाधिक बोझ रिट याचिकाओं का है, जो राज्य और नागरिकों के बीच बढ़ते संवैधानिक और प्रशासनिक विवादों को दर्शाता है।

इन लंबित मामलों में से 1,19,906 प्रकरण ऐसे हैं जो 10 वर्ष से भी अधिक समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनमें 76,964 दीवानी, 35,937 फौजदारी और शेष विविध श्रेणियों के मामले शामिल हैं। यह संख्या न्याय व्यवस्था की मौजूदा चुनौतियों की गंभीरता को उजागर करती है, जिसे दूर करने के लिए न्यायिक नियुक्तियों का यह सिलसिला अहम भूमिका निभा सकता है।

राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या भले ही 50 हो, लेकिन वर्ष 2025 की शुरुआत में यह आंकड़ा 36 पर सिमटा हुआ था, यानी कुल स्वीकृत पदों में 28% रिक्तता बनी हुई थी। अब, सात नए न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के बाद कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है और रिक्त पदों की संख्या घटकर 7 (14%) रह गई है, जो अब तक की सबसे न्यूनतम रिक्तता दर है। वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 48% तक पहुंच गया था।

हड़तालियों ने गाड़ा विरोध का तंबू, एमएलएसयू प्रशासन को पुलिस से उम्मीद, महिला कर्मचारियों ने वीसी और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, उदयपुर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अब धीरे-धीरे हताश हो चुके प्रशासन की ओर से पुलिस की एंट्री करवा कर हड़ताल को तुड़वाने, खत्म करने या फिर फूट डालने का प्रयास हो रहा है। अब तक कोई भी प्रशासनिक या अकादमिक प्रयास नहीं किए गए हैं। केवल डाक्यूमेंट में अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए कर्मचारियों के सेवा एक्सटेंशन का कार्मिक आदेश आनन फानन में जारी कर दिया गया है व अब इसी की आड़ में उल्टा कर्मचारियों को ही दोषी व एमएलएसयू प्रशासन को विक्टिम साबित करने की कोशिश होती दिख रही है। बिगड़ती व्यवस्थाओं के बावजूद पूरे विश्वविद्यालय में ईगो प्राब्लम वाले चैन की बांसूरी बजाकर सो रहे हैं। एसएफएबी कार्मिकों की पांचों मांगों पर सहमति तो दूर उन पर खुलकर चर्चा भी नहीं की गई है। कर्मचारियों की ओर से वीसी का पुतला जलाने के बाद माहौल और गरमा गया है। अब तल्खियां भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस मामले में स्थानीय विधायक व सांसद की चुप्पी के पीछे भी चर्चा का बाजार गर्म है कि उनको किसी उच्च संवैधानिक पद के यहां से फोन आने के बाद चुप रहने, मामले को लगातार अनसुना करने व खुद आकर दखल नहीं देने जैसी कोई हिदायतें दी गई है। इस बात को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि इससे पहले हर बार हड़ताल के समय उनकी निर्णायक मौजूदगी रहीं थी। लेकिन इस बार हर तरह के फीडबैक के बावजूद वे मूकदर्शक की भूमिका में हैं। इधर, आज कर्मचारियों को सुबह प्रशासनिक भवन से बाहर जाने को कहा गया व पुलिस प्रोटेक्शन में कहा गया कि आप संविधान पार्क में जाकर प्रदर्शन करो। इस पर प्रदर्शनकारी आग बबूला हो गए व कहा कि यह विश्वविद्यालय का मामला है। प्रशासन पुलिस के माध्यम से सोल्यूशन का जो प्रयास कर रहा है वह किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। मामला हमारे और प्रशासन के बीच है, इसमें पुलिस का दखल आखिर क्यों? इसके बाद महिला कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला व कहा कि वे किसी भी हाल में अपने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन से दूर नहीं जाएंगी। आखिरकार समझाइश के बाद सबने बाहर आकर धरना शुरू किया। इसके बाद कर्मचारियों की ओर से प्रशासनिक भवन के बाहर ही तंबू लगा दिया गया व ऐलान किया गया कि जब तक न्याय नहीं होगा हड़ताल जारी रहेगी। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की व कहा कि अब पूरा प्रशासन पुलिस कार्रवाई पर फोकस कर रहा है। उन्हें उम्मीद है कि वहां से समाधान निकल जाएगा। कर्मचारी बोले कि अध्यक्ष नारायण सालवी को प्रतापनगर थानाधिकारी की ओर से नोटिस दिया जाना इसी ओर संकेत करता है कि अब सुविवि प्रशासन में अपने रसूखात का उपयोग करके पुलिसिया कार्रवाई करने पर आमादा हो गया है। किसी न किसी प्रकार से कर्मचारियों ने डराने या प्रयास किया जा रहा है ताकि भयभीत होकर चुपचाप हड़ताल तोड़ काम पर चले जाएं। कर्मचारियों की ओर प्रेसवार्ता का आयोजन भी किया गया जिसमें बताया गया कि संविदा /एस.एफ.एस. कर्मी लगभग पिछले 25 वर्षों से भी अधिक समय से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर की विभिन्न इकाईयों में नियमित सेवा देते आ रहे है। किंतु जब से प्रो. सुनीता मिश्रा ने कुलपति का पद संभाला है तब से स्वः वित्तपोषित सलाहकार मंडल से दिक्कत है। जबकि विश्वद्यालय के नियमानुसार बनाए गए सेल्फ फाइनेंस एडवाइजरी बोर्ड के माध्यम से नियुक्ति दी जाती है। पहले विज्ञापन, फिर लिखित परीक्षा और अंत में साक्षात्कार के माध्यम से सिलेक्शन किया जाता है। पहले 6 महीने और उसके बाद 5 महीने का वर्क ऑर्डर और फाइनेंशियल ऑर्डर निकलता था। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन 1 जनवरी 2025 के बाद कभी एक महीने का तो कभी दो महीने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करता है। कभी वित्तीय स्वीकृति वित्त नियंत्रक के द्वारा कर्मचारियों द्वारा एक से डेढ महीने का कार्य करने के बाद जारी की जाती है। संविदा/एस.एफ.एस.कर्मियो का कार्यकाल 30 जून, 2025 तक बढाया गया था। इसके पश्चात् कर्मचारियों ने कार्यकाल बढाने के लिए कुलपति व कुल सचिव को लिखित पत्र के माध्यम से आगे का कार्य विस्तार बढाने के लिए अवगत किया गया। लेकिन प्रशासन की हथधर्मिता व अहंकार के कारण कार्य विस्तार बढाने से आनाकानी कर रहे थे। 13 दिन तक इंतजार करने के बाद जब किसी भी तरह का आदेश जारी नहीं हुआ तो मजबूरी में सभी सेवा प्रदाताओं को धरने पर बैठना पड़ा। जबकि राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग से जारी पत्र क्रमांक प.07 (1) शिक्षा-4 / 2024 04463 -6350529 24 जनवरी, 2025 को डॉ. हरिशंकर मेवाडा, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा जारी सचिव, सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नाम जारी प्रेषित परिपत्र में स्वः वित्तपोषित सलाहकार मंडल के तहत विभिन्न सेवा प्रदाताओं की सेवाऐं 01 जनवरी, 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक का कार्यकाल बढाने की स्वीकृति जारी कर दी हैं स्ववित्त पोषित सलाहकार बोर्ड के अन्तर्गत कार्य करने वाले सेवा प्रदाताओं द्वारा सोमवार 14 जुलाई से अपने पांच सूत्रीय मांगों के साथ शांतिपूर्ण धरने पर बैठे है मगर वह भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है।

महिला कर्मचारियो ने दोहरा-वीसी झूठ बोल रही, हमने उनके यहां काम किया

महिला कर्मचारियों ने फिर दोहराया कि हमने वीसी मैडम के यहां पर काम किया हैं। वीसी इसे झुठला नहीं सकती। हमें बकायदा वहां पर जिन्होंने भेजा था उनके नाम भी बता सकते हैं। वहां पर काम करने व आने जाने के दौरान हुई एंट्री के दस्तावेज भी मौजूद हैं। वीसी मैडम आखिर इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है यह आश्चर्य की बात है। उन्होंने प्रतापनगर थाना पुलिस पर भी आरोप लगाया कि परिवाद देने के बाद भी आज तक ना तो कोई पूछताछ हुई है ना एफआईआर की गई है। उल्टे दबाव बनाने प्रयास पुलिस की ओर से किया जा रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय व राज्य महिला आयोग को इसकी शिकायत की है। वहां से कार्रवाई की उम्मीद है।

भामस का स्थापना दिवस मनाया

कर्मचारियों ने अपने पैत्रक संगठन भामस का स्थापना दिवस मानते हुए धरना स्थल पर ही भारत माता के जयकारों के बीच आरएसएस व भामस के गीतों का सस्वर व समवेत गायन भी किया तथा कहा कि डबल इंजन के सरकार होते हुए भी राष्ट्रवादी संगठन से जुड़े एसएफएबी कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है।

डबोक एयरपोर्ट स्थित श्री श्याम मंदिर निर्माण को एक वर्ष पूर्ण, 30 अगस्त को झूलोत्सव कीर्तन का होगा भव्य आयोजन

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट द्वारा डबोक एयरपोर्ट के पास तुलसीदास सराय में निर्मित हो रहे राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े भव्य श्याम मंदिर के निर्माण कार्य को एक वर्ष पूर्ण हो चुका है। इस एक वर्ष में श्रद्धा, समर्पण और सेवा के साथ जिस गति से निर्माण कार्य हुआ है, वह आश्चर्यजनक और प्रेरणादायक है। प्रमुख ट्रस्टी अशोक पोद्दार ने जानकारी दी कि 24 जुलाई 2024 को मंदिर के गर्भगृह में वृंदावन के आचार्य ब्रजेश महाराज सहित पांच पंडितों के सान्निध्य में पूजा संपन्न हुई थी। तत्पश्चात, तत्कालीन कलेक्टर अरविंद पोसवाल, वर्तमान एसपी योगेश गोयल सहित कई गणमान्य नागरिकों, ट्रस्टीगण एवं श्रद्धालुओं ने शिलाओं को सिर पर धारण कर गर्भगृहों में प्रतिष्ठापित किया। मंत्रोच्चार के बीच गणेशजी, हनुमानजी, शंकरजी, राणी सती दादी एवं खाटू श्यामजी के मंदिरों की शिलाएं 11 फीट गहराई में स्थापित की गईं, जिससे पूरा परिसर "जय श्री श्याम" और "हारे के सहारे की जय" के नारों से गूंज उठा।

सचिव प्रताप नारायण गुप्ता के अनुसार, निर्माण कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। 10 जून 2025 को राम मंदिर की तर्ज पर सांसद, विधायक, कलेक्टर, डीआईजी, एसपी, एडीएम, आईएएस, आईपीएस अधिकारियों, ट्रस्टीगण एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में विशेष पूजा के बाद 5 मंदिरों के आधार शिलाएं 21 फीट ऊंचाई पर स्थापित की गईं। यही स्थान भविष्य में भगवान के चरण कमलों की प्रतिष्ठा के लिए तय किया गया है।

ट्रस्टी उमेश दाधीच ने बताया कि एक वर्ष पूर्व 24 जुलाई को आयोजित सावनोत्सव झूलोत्सव कीर्तन में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बना था।

तब से लेकर अब तक हर माह कीर्तन आयोजन लगातार हो रहा है, भले ही अनेक बाधाएं आई हों।

ट्रस्टी राजू शर्मा ने बताया कि मंदिर 1,17,000 वर्गफुट क्षेत्रफल में निर्मित होगा, जिसमें मुख्य मंदिर का फ्लोर एरिया 13,000 स्क्वायर फीट होगा और नीचे 9,000 स्क्वायर फीट का हाल बनाया गया है, जहां इस माह से नियमित कीर्तन प्रारंभ हो गया है। मंदिर की कुल ऊंचाई 91 फीट होगी, जो मुख्य हाइवे से 20 फीट ऊपर रहेगा, जिससे सड़क से भी मंदिर के दर्शन संभव होंगे।

एन. एल. खेतान ने बताया कि अब से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ने लगी है। मंदिर निर्माण में वही पत्थर उपयोग हो रहे हैं जो अयोध्या के श्रीराम मंदिर में लगे हैं, जिन्हें बांसी भरतपुर से मंगाया जा रहा है।

ट्रस्टी अमिताभ गोयल ने बताया कि परिसर में गौशाला, 100 कमरों की धर्मशाला, वृद्धाश्रम और 30,000 स्क्वायर फीट का भव्य गार्डन भी बनाया जाएगा। कोषाध्यक्ष विष्णु रांदड़ ने आशा जताई कि मंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 2026 तक पूर्ण हो जाएगा।

एक वर्ष पूर्ण होने पर 30 अगस्त को विशेष झूलोत्सव कीर्तन बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर जयपुर के सांवरिया डेकोरेटर प्रतिमास मंदिर को विविध श्रृंगारों से सजाते हैं। उमेश म्यूजिकल ग्रुप नीमच कीर्तन में संगीत संगत करता है, जबकि हिमांशु साउंड और अनिल वैद्य द्वारा पंडाल, दरबार एवं रंग-बिरंगी रोशनियों से मंदिर परिसर को जगमगाया जाता है। अध्यक्ष शशिकांत ने इस अवसर पर सभी ट्रस्टीगण, कार्यकर्ताओं, श्याम प्रेमियों, श्रद्धालुओं और मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए हार्दिक प्रशंसा और बधाई दी।

निंबाहेड़ा को मुख्यमंत्री ने किया 167 कार्यों का शिलान्यास, 67 का लोकार्पण, चाय की दुकान पर रुके, UPI से किया भुगतान

24 न्यूज अपडेट

रिपोर्ट-कविता पारख निंबाहेड़ा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को निंबाहेड़ा दौरे के दौरान करीब 700 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। बारिश के चलते वे उदयपुर से हेलिकॉप्टर द्वारा निंबाहेड़ा कॉलेज ग्राउंड स्थित हेलीपैड पहुंचे, जहां आयोजित जन आशीर्वाद समारोह में विधायक श्रीचंद कृपलानी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। देवी अहिल्या बाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री ने कृषि उपज मंडी परिसर में स्थापित साढ़े चार क्विंटल वजनी देवी अहिल्या बाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने 167 विकास कार्यों का शिलान्यास और 67 कार्यों का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा, "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। सरकार संकल्प पत्र पर कर रही है कामः मुख्यमंत्री सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संकल्प पत्र को धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी योजना के जरिए राज्य में पेयजल संकट को दूर करने का प्रयास हो रहा है और बांसवाड़ा, राजसमंद जैसे जिलों को जोड़ने के लिए आधारभूत संरचनाओं पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुई परीक्षा पेपर लीक घटनाओं से युवाओं का भरोसा टूटा था, जिसे पुनः स्थापित करने के लिए वर्तमान सरकार ईमानदारी से कार्य कर रही है। कार्यक्रम स्थल पर 20 प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए, जिनमें 18 स्टॉल विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित थे, जबकि 2 स्टॉल सीमेंट उद्योगों की CSR गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए रखे गए।

साधारण नागरिकों से जुड़ावः दुकान पर चाय पी, UPI से किया भुगतान

कार्यक्रम के बाद लौटते समय मुख्यमंत्री का काफिला अहिंसा सर्किल के पास एक स्थानीय चाय की दुकान पर रुका। मुख्यमंत्री ने वहां चाय पी और दुकानदार को UPI के माध्यम से भुगतान कर डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित किया। इस सहज व्यवहार ने आमजन से उनका सीधा जुड़ाव भी प्रदर्शित किया।

पर्ची सरकार जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का कर रही हनन, कानून व्यवस्था चौपटः कांग्रेस का आरोप

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 23 जुलाई। राजस्थान में भाजपा की "पर्ची-खर्ची सरकार" पर हमला तेज करते हुए उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को सब सिटी सेंटर स्थित काग्रेस कार्यालय में बैठक कर राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला। बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, स्थानीय निकायों के चुनावों में देरी और स्मार्ट मीटर थोपे जाने के विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया और जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। "निकाय चुनाव टालकर लोकतंत्र का कर रही हनन" – इंदिरा मीणा बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार भाग लेने आईं उदयपुर देहात जिला कांग्रेस प्रभारी एवं विधायक इंदिरा मीणा ने कहा, "पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के तहत हर पांच वर्ष में कराना अनिवार्य है, लेकिन पर्ची सरकार जानबूझकर इन चुनावों को टालकर जनप्रतिनिधियों के अधिकार छीन रही है। कई निकायों का कार्यकाल पूरा हुए 12 महीने से अधिक हो चुके हैं, फिर भी चुनाव नहीं कराए गए।" उन्होंने कहा कि यह सीधे-सीधे लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। कांग्रेस पार्टी इस तानाशाही रवैये का विरोध करते हुए स्थानीय निकायों और पंचायतों के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी। "स्मार्ट मीटर लगवाने की नौटंकी बंद करे सरकार" – कचरू लाल चौधरी उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष कचरू लाल चौधरी ने कहा कि, "पर्ची सरकार आमजन से जुड़ी समस्याओं को दरकिनार कर उन्हें स्मार्ट मीटर थोपने में लगी है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। मंत्री और विधायक यदि ईमानदार हैं तो पहले अपने-अपने निजी घरों में स्मार्ट मीटर लगवाकर सोशल मीडिया पर फोटो डालें, न कि सरकारी आवास पर, जहां बिल खुद सरकार देती है।" उन्होंने मांग की कि सरकार पहले यह स्पष्ट करे कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता का बिजली बिल नहीं बढ़ेगा और क्या इसमें निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिलता रहेगा।

"कानून व्यवस्था के नाम पर अराजकता" – ताराचंद मीणा पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने कहा कि, "बीते डेढ़ वर्ष में प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार, लूटपाट, डकैती, बलात्कार, चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। बजरी माफिया खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज प्रदेश में नजर नहीं आती।" उन्होंने चेताया कि यदि हालात नहीं सुधरे तो कांग्रेस कार्यकर्ता आमजन की पीड़ा को लेकर सड़क से सदन तक पर्ची सरकार को घेरेंगे।

ज्ञापन सौंपकर जताया विरोध

बैठक के उपरांत जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इसमें निकाय व पंचायत चुनाव शीघ्र करवाने, स्मार्ट मीटर के खिलाफ पारदर्शी नीति अपनाने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, बजरी माफियाओं पर कार्रवाई और कानून व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई।

बैठक में शामिल प्रमुख नेता और कार्यकर्ता

बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री डॉ. मांगीलाल गरासिया, पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत, बसंती देवी मीणा, मावली विधायक पुष्कर डांगी, पीसीसी उपाध्यक्ष हीरा लाल दरांगी, पीसीसी महासचिव लाल सिंह झाला, पूर्व जिला प्रमुख ख्यालीलाल सुहालका, कांग्रेस प्रत्याशी विवेक कटारा (उदयपुर ग्रामीण), रेशमा मीणा (सलूंबर उपचुनाव), पीसीसी सदस्य रामलाल गायरी, देहात कांग्रेस संगठन महासचिव गजेंद्र कोठारी, प्रवक्ता डॉ. संजीव राजपुरोहित, ब्लॉक अध्यक्ष गुलाब सिंह राव, राम सिंह चदाणा, ओनार सिंह सिसोदिया, कमल डांगी, रूपलाल मीणा, राजेंद्र गोखरू, खेमराज मीणा, राजेंद्र जैन, रायसाराम खैर, गणेश चौधरी, लक्ष्मण सिंह राठौड़, महेंद्र सिंह राणावत, देहात कांग्रेस अध्यक्ष मोहब्बत सिंह राणावत, प्रधान गंगाराम मीणा, कमला परमार, पुष्पा मीणा, राधा देवी परमार, युवा कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष बालू लाल भील, ओबीसी विभाग अध्यक्ष कमलेश पटेल, कांग्रेस उपाध्यक्ष मोड़ सिंह सिसोदिया, नवल सिंह चुंडावत, महासचिव लक्ष्मीनारायण मेघवाल, भगवानलाल अहीर, श्याम सुंदर आमेटा, महेश त्रिपाठी, भूपेंद्र चौहान, दिनेश औदिच्य, पूर्व पार्षद मदन सिंह बाबरवाल, जिला परिषद सदस्य कामिनी गुर्जर, दिव्यानी कटारा, सचिव भानु गुर्जर, चंद्रवीर गुर्जर, शंकरलाल मेघवाल, टीटू सुथार, मोतीलाल शर्मा, महेंद्र डामोर, एनएसयूआई के शक्ति सिंह झाला, किशन सिंह चुंडावत, धनपाल जैन, गोपाल सरपटा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

भीलवाड़ा जिले के 17 बांध हुए ओवरफ्लो, खेतों में बुवाई भी भरपूर

24 न्यूज अपडेट

भीलवाड़ाः इस मानसून में जिले में भारी वर्षा हुई. इस कारण सिंचाई विभाग के तहत आने वाले 60 बांधों में से 17 ओवरफ्लो हो चुके हैं, जबकि एक बांध लबालब हो गया है. साथ ही जिले से गुजरने वाली त्रिवेणी नदी तीव्र गति से बह रही है. जिससे बीसलपुर बांध के लबालब होने की संभावना है. अब तक जिले में सबसे अधिक वर्षा बिजोलिया क्षेत्र में दर्ज की गई है.

इस बार मानसून की अच्छी गतिविधि के कारण नदियों और तालाबों में पर्याप्त जलभराव हुआ है. जुलाई में लगातार वर्षा होने से किसानों ने खरीफ फसलों जैसे मूंग, उड़द, तिल, ग्वार, ज्वार, मक्का, बाजरा और सोयाबीन की बुवाई अच्छी मात्रा में की है. भीलवाड़ा कृषि विभाग ने इस साल 4 लाख 60 हजार हेक्टेयर भूमि में खरीफ फसलों की बुवाई का लक्ष्य रखा था, जो अब तक लगभग पूरा हो चुका है. हालांकि, कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण फसलों को नुकसान भी हुआ है.

17 बांध भरेः भीलवाड़ा सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता सोजी सिंह प्रतिहार ने बताया कि जिले के 60 बांधों में से 17 ओवरफ्लो हो चुके हैं, जबकि पचानपुरा बांध लबालब हो गया है, शेष बांधों में 33% जल संग्रहित है. उन्होंने कहा कि बांधों की निगरानी के लिए फील्ड अधिकारियों को तैनात किया गया है. बागोर में सबसे कम बारिशः जिले में अब तक सबसे कम वर्षा मांडल विधानसभा क्षेत्र के बागोर में 38 मिलीमीटर दर्ज की गई है. जिले में सबसे अधिक वर्षा बिजोलिया तहसील के जैतपुरा क्षेत्र में हुई है. अब तक भीलवाड़ा जिले में 417.91 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि जिले का औसत वार्षिक वर्षा स्तर 601 मिलीमीटर है. इस प्रकार, अब तक 70% वर्षा हो चुकी है.

24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक - सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा ।